0 सिर्फजेनेरिक दवाएँ खरीदी जायेंगी, चिकित्सक जेनेरिक दवाएँ ही लिखें - मुख्यमंत्री

म.प्र. में खोले जायेंगे 1000 जन औषधि केन्द्र - मण्डाविया

0 लोगों को मिलेंगी सस्ती दवाइयाँ, मात्र 72 घंटे में जन औषधि केन्द्रों पर उपलब्ध होंगी जेनेरिक दवाएँ

भोपाल 13 सितम्बर (ए) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरूआत क्रांति का शंखनाद है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब जेनेरिक दवाएँ खरीदी जायेंगी। जेनेरिक दवाओं के उपयोग और असर से संबंधित भ्रांतियाँ दूर करने के लिये जन.जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने सभी चिकित्सकों से आग्रह किया कि वे कंपनी की दवाएँ लिखने के साथ जेनेरिक दवाएँ भी लिखें। उन्होंने कहा कि भारतीय जन औषधीय परियोजना का क्रियान्वयन जन अभियान परिषद करेगी। उन्होंने जन हितैषी योजना के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। चौहान ने कहा?कि चिकित्सकीय सुविधाओं और दवाओं के संबंध में अतिशयोक्तिपूर्ण विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिये भी कदम उठाये जाना चाहिये।

मुख्यमंत्री चौहान आज यहाँ प्रशासन अकादमी में राज्य सरकार और केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के बीच जन औषधि केन्द्र शुरू करने के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद जेनेरिक औषधि के उपयोग पर कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। राज्य शासन की ओर से जन अभियान परिषद के कार्यपालक निदेशक उमेश शर्मा और भारत सरकार की ओर से ब्यूरो आफ फार्मा पीएसयू के सीईओ विप्लव चटर्जी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये। उल्लेखनीय है कि जेनेरिक दवाइयाँए ब्राण्डेड व महंगी दवाइयों की तुलना में अत्यंत किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। इनके घटक एवं रचनाएँ एक जैसी होती हैं। अन्य किसी भी ब्राण्डेड की तुलना में इन दवाइयों का कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता।

चौहान ने कहा कि जेनेरिक दवाओं के लाभ को जनता के सामने लाना होगा। उन्होंने कहा कि गरीबों का सही समय पर असरकारक और सस्ता इलाज होना चाहिये। इससे बीमारी में लगने वाला पैसा बचेगा और जनता को बड़ी राहत मिलेगी।

.मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा . केन्द्रीय राज्य मंत्री मण्डाविया

केन्द्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मण्डाविया ने मुख्यमंत्री चौहान को नवाचारी मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि मध्यप्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। यह गरीबों की सेवा और गरीबोन्मुखी योजनाएँ बनाने के लिये जाना जाता है।

मण्डाविया ने कहा कि जेनेरिक दवाओं और कंपनी की ब्रांडेड दवाओं में सिर्फ कंटेट का फर्क होता है। ब्रांडेड दवाएँ नाम से बिकती हैं। उन्होंने कहा कि जनौषधि परियोजना गरीबों की सेवा के लिये है।

मण्डाविया ने कहा कि भारत में बन रही जेनेरिक दवाएँ गुणवत्ता से भरपूर हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुमोदित हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने हृदय रोग के लिये काम आने वाले स्टेण्ट की कीमत बहुत कम कर दी है जो लाखों में होती थी। उन्होंने कहा कि जेनेरिक दवाओं के कारण केवल दो साल में जनता का 8400 करोड रूपये बचा हैए जो महंगे इलाज में खर्च होता। उन्होंने बताया कि जन औषधि केन्द्रों में जेनेरिक दवाओं के प्रदाय की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था की जा रही है। औषधिक केन्द्रों में दवाओं का स्टाक कम होते ही केन्द्रीय प्रदाय तंत्र तक सूचना पहुँच जायेगी और मात्र 72 घंटे के अंदर जन औषधि केन्द्रों पर स्टाक पहुँच जायेगा। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में 1000 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य तय किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री रूस्तम सिंह ने कहा कि जन औषधि केन्द्रों से जरूरतमंद गरीब परिवारों को बहुत राहत मिलेगी।

.मिलेंगे रोजगार के अवसर

जेनेरिक दवाइयों के स्टोर खुलने से प्रदेश स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही योजनांतर्गत जेनेरिक स्टोर खोलने वाले व्यक्ति को जेनेरिक दवाइयों पर अनुदान के रूप में 24 माह तक प्रतिमाह 10 हजार के मान से कुल 2 लाख 50हजार का वित्तीय सहयोग भी दिया जायेगा। दवाइयों की बिक्री पर डिस्ट्रीब्यूटर को 10 प्रतिशत एवं रिटेलर को 20 प्रतिशत का लाभ प्राप्त होगा।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव योजना दीपक खांडेकर एवं भारतीय जन औषधि परियोजना के अधिकारी उपस्थित थे। जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे ने आभार व्यक्त किया।

चेतावनी के बावजूद मात्र 121 करोड़ की वसूली

0 अधिकारियों को उल्टा टांगने की चेतावनी बेअसर

भोपाल 13 सितम्बर (ए) काम नहीं करने वालों को उल्टा टांगने की चेतावनी भी बेअसर साबित हो रही है। चेतावनी के बावजूद 1111 करोड़ रुपए के नजूल व डायवर्सन शुल्क के बदले कलेक्टर सिर्फ 121 करोड़ रुपए की ही वसूली करा सके हैं। कलेक्टर सरकार की कोशिश के बाद भी इन मदों में शुल्क वसूली नहीं करा सके हैं। इन हालातों को देखते हुए मुख्य सचिव बीपी सिंह ने सभी कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी है कि इस काम की समीक्षा करें और वसूली में लगातार सुधार कराएं। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान राज्य शासन के संज्ञान में यह बात सामने आई है कि कलेक्टर जिलों में शहरी क्षेत्रों में लोगों व संस्थाओं को एक निश्चित प्रीमियम व भू भाटक तथा भूमि उपयोग बदलने के बदले लगने वाले डायवर्सन शुल्क की वसूली नहीं करा पा रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि चालू साल में अप्रेल से अब तक 5 माह में सिर्फ 11 फीसदी राशि की ही वसूली की जा सकी है। यह स्थिति चिंताजनक है जिससे कलेक्टरों को नोटिस देने का प्रस्ताव राजस्व विभाग के अफसरों ने शासन को भेजा है। सूत्रों का कहना है कि चूंकि मुख्य सचिव ने पिछले माह संभागीय समीक्षा के दौरान खुद भी इस तरह की स्थिति को भांपा है और उन्होंने स्थिति सुधारने के लिए दो माह का समय दिया है। इसलिए फिलहाल किसी कलेक्टर विशेष को नोटिस तो जारी नहीं किया गया पर संभागायुक्तों और कलेक्टरों को संबोधित चिट्ठी सीएस सिंह ने लिखी है।

कलेक्टरों से कहा है कि वे इसकी सतत समीक्षा कराएं और डायवर्सन व नजूल रेंट की वसूली समय पर कराएं। अधीनस्थ अधिकारियों के काम की प्रगति वे देखते रहें। जमीन के डायवर्सन शुल्क की सबसे अधिक राशि बड़े शहरों इंदौरए भोपालए ग्वालियरए जबलपुर में ही ज्यादा है। इसके अलावा जिन शहरों का प्लान एरिया बढ़ रहा है और बिल्डरए कॉलोनाइजर व इंडस्ट्री वहां पहुंच रही हैंए वहां जमीन का कृषि उपयोग आवासीयए सार्वजनिक तथा आवासीय कम सार्वजनिक प्रयोजन के लिए होने की अनुमति दी जा रही है। इसके लिए होने वाली डायवर्सन शुल्क की बकाया राशि जमा कराने में गड़बड़ की जाती है। सूत्रों का कहना है कि जांच होने की दशा में भोपाल व इंदौर में कालेजए नई कालोनियों का निर्माण करने के बदले जमा होने वाली राशि में गड़बड़ी की स्थिति भी बन सकती है क्योंकि यहां सर्वाधिक डायवर्सन के मामले सामने आए हैं। डायवर्सन व नजूल की वसूली के मामले में ही इंदौर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तवए अजीत श्रीवास्तवए संदीप सोनी तथा तहसीलदार राजेश सोनी और दर्शिनी सिंह को सस्पेंड किया गया था।

सरकार ने नहीं पढ़ा 13 किलोमीटर लंबा ज्ञापन

भोपाल 13 तितंबर (ए) मण्प्र के शासकीय कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डेढ किलोमीटर लंबा एक ज्ञापन तैयार किया था। इस ज्ञापन को कर्मचारियों ने सरकार को सौंपा था। यह ज्ञापन सरकार के अधिकारियों ने लेकर बल्लभ भवन की चौथी मंजिल के कारीडोर में लावारिस हालत में डाल दिया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस ज्ञापन को पढ़ने की व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। यह बल्लभ भवन के गलियारे की शोभा बना हुआ है।।

सरपंच से रिश्वत मांगने वाले इंजीनियर को लोकायुक्त ने दबोचा

भोपाल 13 सितम्बर (ए) राजधानी लोकायुक्त पुलिस ने विदिशा जिले में कार्यवाही करते हुए उपयंत्री को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगें हाथों पकड़ लिया गया है। आरोपी ने यह रकम निर्माण कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र देने के ऐवज में सरपंच से मांगी थी। लोकायुक्त अफसरों ने बताया कि आरोपी उपयंत्री अंकित पाठक उपयंत्री के पद पर मनरेगा जनपद पंचायती लटेरी जिला विदिशा में पदस्थ् है। क्षेत्र की ग्राम पंचायत रुसल्ही साहू में सीमेंट क्रांक्रीट रोड का कार्य किया गया था। इस कार्य के पूरा होने पर कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र सरपंच को देने के बदले में उपयंत्री अंकित पाठक द्वारा सरपंच के प्रतिनिधि धनराज सिंह बघेल निवासी रुसल्ही साहू में बीस हजार रुपये की रिश्वत मांगी गई थी जिसकी शिकायत धनराज द्वारा लोकायुक्त टीम को बीते दिनों की गई थी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त टीम ने योजना बनाई जिसके बाद फरियादी की उपयंत्री से बातचीत कराने के बाद उसे रिश्वत की रकम लेकर उसके पास भेजाद्य वैसे ही अंकित पाठक ने रिश्वत की रकम अपने कब्जे में ली वहां जाल विछाकर बैठी लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया।

भोपाल में सहकारिता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार विश्वास सारंग जन.संवाद पदयात्रा के तीसरे दिन मंगलवार को बौद्ध विहार पहुंचकर नागरिकों से मिले।

अपर आयुक्त ने की जनसुनवाई

भोपाल13 सितम्बर (ए) नागरिको की मूलभूत सुविधाओं संबंधित शिकायतों समस्याओं के त्वरित निराकरण के दृष्टिगत आयोजित की जाने वाली जनसुनवाई के क्रम में इस मंगलवार को अपर आयुक्त प्रदीप जैन ने हर्षवर्धन कॉम्प्लेक्स माता मंदिर स्थित निगम मुख्यालय में जनसुनवाई की और नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण की कार्यवाही करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया तथा शिकायत संबंधी आवेदनों को अग्रेषित किया। इस दौरान नागरिकों ने व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उपस्थित होकर 20 आवेदन प्रस्तुत किए।

अपर आयुक्त प्रदीप जैन ने निगम मुख्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान नागरिकों ने तात्या टोपे नगर दशहरा मैदान के समीप एवं कॉरीडोर में किए गए अतिक्रमणों को हटाने सड़क एवं नाली निर्माण कराने अवैध निर्माण हटानेए पेंशन प्रकरण का निराकरण करानेए स्ट्रीट लाईट लगवानेए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुटीर प्रदान करने शूज मार्केट के दुकानदारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने कोलार मेन रोड बंजारी चौराहा के पास से अतिक्रमण हटाने नेहरू नगर में सांईधाम के सामने आवासीय भूखण्डों का व्यवसायिक उपयोग एवं अवैध निर्माण की जांच करानेए दिव्यांग पेंशन प्रदान करनेए मजदूरी कार्ड बनवाने के अलावा भवन अनुज्ञा जलकार्य राजस्व आदि संबंधी समस्याओं शिकायतों से अवगत कराया जिस पर अपर आयुक्त जैन ने नागरिकों की शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया एवं आवेदनों को भी संबंधित अधिकारियों की ओर अग्रेषित किया। जनसुनवाई के दौरान निगम के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।

छठी ड्रॉप रोबॉल में एलएनसीटी उपविजेता

भोपाल 13 सितम्बर (ए) छठी सीनियर ड्रॉप रोबॉल स्टेट चैंपियनशिप में एलएनसीटी की महिला खिलाडियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता होने का गौरव हासिल किया।

ट्रिपल में स्वीटी चौरसियाए अंकिता जैन और प्रियंका वर्मा की तिकड़ी ने रायसेन दुर्गा राजपूतए रूकमिणी भिलाला और विद्या की टीम को 21.12ए 16.21ए 21.18 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। वहीं डबल्स में एलएनसीटी की रितु मिश्रा और नंदिनी सोनी की जोड़ी ने भोपाल की ज्योति एवं शीतल की जोड़ी को 21.9ए 21.18 से हराकर स्वर्ण जीता।

रायसेन ने दो स्वर्णए तीन रजत और एक कांस्य पदक जीतकर चैंपियनशिप प्रथम स्थान हासिल किया। एलएनसीटी दो स्वर्ण के साथ दूसरे और एक रजत और तीन कांस्य के साथ भोपाल टीम तीसरे स्थान पर रही। पुरुष वर्ग के ट्रिपल में एलएनसीटी के रिषि श्रीवास्तवए दीप राज और अभिषेक की तिकड़ी ने कांस्य पदक प्राप्त किया। संस्था के पदक विजेता खिलाडियों को मप्र ड्रॉप रोबॉल संघ के अध्यक्ष एवं एलएनसीटी ग्रुप के सचिव डॉण् अनुपम चौकसे, ओएसडी डॉण् अशोक रायए प्राचार्य डॉण्अशोक मोवार और खेल अधिकारी पंकज जैन ने बधाई दी है।

स्टेट चैंपियनशिप का आयोजन बुधनी में किया गया। इसमें होशंगाबादए सिंगरौलीए सतनाए जबलपुरए इंदौरए मंदसौरए धारए रायसेनए छिंदवाड़ाए भोपालए सीहोरए टीकमगढ़ए विदिशा और नरसिंहपुर की टीमों ने हिस्सा लिया।

करोड़ों चुकाए बगैर व्यापारी फर्म समेत गायब

भोपाल 13 सितम्बर (ए) प्रदेश के कई संभागों के व्यापारी करोड़ों का बकाया चुकाए बगैर फर्म समेत गायब हो गए हैं। इन व्यापारियों में प्रदेश के सागर, रीवा, शहडोल चंबल.ग्वालियर के व्यापारी शामिल है। इन भगोडे व्यापारियों से राज्य सरकार को वैट तथा अन्य रूप में मोटी रकम वसूलनी थी। इन व्यापारियों को नोटिस दिए जा रहे थे। ऐसे व्यापारियों ने अब यूपी छत्तीसगढ़ गुजरात समेत अन्य राज्यों में दूसरी फर्मों के नाम से कारोबार शुरू कर दिया है। हालांकि कामर्शियल टैक्स विभाग का कहना है कि जीएसटी लागू होने के बाद ऐसे व्यापारियों को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मालूम हो कि एक जुलाई से पूरे देश में एक कर प्रणाली जीएसटी लागू होने के बाद विन्ध्य क्षेत्र के सिंगरौली सतना रीवा अनूपपुर शहडोल सागर संभाग के टीकमगढ़ सागर छतरपुर चंबल ग्वालियर संभाग के ग्वालियर मुरैना समेत अन्य जिलों से सैकड़ों व्यापारी अपनी फर्मों के साथ गायब हो गए हैं।

सूत्रों का कहना है कि इन व्यापारियों पर 25 करोड़ रुपए से अधिक का टैक्स वैट एक्साइज एंट्री टैक्स समेत अन्य रूप में बकाया है। ऐसे व्यापारियों द्वारा पड़ोसी राज्यों में दूसरी फर्मों के नाम से पंजीयन कराकर कारोबार शुरू किए जाने की सूचना कामर्शियल टैक्स अधिकारियों को मिली है। सूत्रों का कहना है कि बकायादारों से वसूली के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं पर राशि जमा नहीं हो रही है। हालांकि वित्त मंत्री जयंत मलैया से इस बारे में चर्चा करने पर उन्होंने कहा कि जो व्यापारी यहां काम बंद करके गए हैंए उन्होंने देश तो नहीं छोड़ा है। इधर वित्तमंत्री जयंत मलैया ने पिछले दिनों हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह प्रस्ताव रखा है कि डेढ़ करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को राहत दी जाए। साथ ही जीएसटी करने की समय सीमा हर माह से बदलकर तीन माह की जाए। मामले में मंत्री मलैया ने कहा कि काउंसिल ने इस सुझाव पर सैद्धांतिक सहमति तो दी है पर यह बात भी सामने आई कि इसे बदलने के लिए कई सारे नियमों में बदलाव करने पड़ेंगे।

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग, दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा

-::निविदा संशोधन सूचना::-

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा विज्ञप्ति क्रमांक 06/व.ले.लि./17-18 दन्तेवाड़ा, दिनांक 19/08/2017 में अपरिहार्य कारणों से निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्रमांक	विवरण	तिथि पूर्वानुसार	संशोधित तिथि
01	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	04/09/2017	18/09/2017
02	निविदा प्रपत्र कार्यालय में पहुँचने की अंतिम तिथि	11/09/2017	25/09/2017
03	निविदा खोलने की तिथि	12/09/2017	26/09/2017

निविदा में निहित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि., दक्षिण बस्तर संभाग, दन्तेवाड़ा

जी-44202

कार्यालय कलेक्टर,जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ.ग.)
(जिला निर्माण समिति)

// मैनुअल पद्धति निविदा सूचना द्वितीय बार //
-: निविदा क्रमांक-06:-

क्रमांक/325/जि.नि.स./ग्रा.या.सेवा/2017 , दन्तेवाड़ा दिनांक-7/09/2017

01. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है :-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू.लाख में)	निविदा प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि
1	2	3
(1)जोनल निविदा जनपद पंचायत कुआकोंडा अंतर्गत	100.00 लाख	26/09/2017

2. उपरोक्त निर्माण कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें,धरोहर राशि,विस्तृत निविदा विज्ञप्ति,निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में नोडल अधिकारी/कार्यपालन अभियंता,(जिला निर्माण समिति) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा में उपस्थित होकर दिनांक 11/09/2017 से लिया जा सकता है।

कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा(छ.ग.)

जी-44212

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा,
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ.ग.)

मो.नं.-09479036821 ई मेल पता:-ee-res.Dantewada@nic.in

// मैनुअल पद्धति निविदा सूचना तृतीय बार //
-: निविदा क्रमांक-02:-

क्रमांक/1403/व.ले.लि/ग्रा.यां.सेवा/2017, दन्तेवाड़ा दिनांक 07/09/2017

1. एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित आंतरिक विद्युतीकरण कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रू. लाख में)	निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि
आंतरिक विद्युतीकरण कार्य		
(1) जोनल विदि-जनपद पंचायत दन्तेवाड़ा अंतर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत भवन निर्माण कार्यों में आंतरिक विद्युतीकरण कार्य	10.00 लाख	19/09/2017

2. उपरोक्त कार्यो की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी विभागीय वेब साईट http://cg.nic.in/resworks में दिनांक 08/09/2017 से निशुल्क डाऊनलोड की जा सकती है।

कार्यपालन अभियन्ता
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग दन्तेवाड़ा
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा(छ.ग.)

जी-44209